



NaMo 25 · #25YearsofSeva

THEN & NOW · 2014 → 2026

तब और अब

एक ही संकेतक, दो तिथियाँ — 2014 और आज। हर आँकड़ा तिथि सहित, क्षेत्रवार।

7 अक्टूबर 2001 → 7 अक्टूबर 2026 · 25 साल, ज़ीरो ब्रेक · 25YearsofSeva.com · संस्करण 88 · 7 अक्टूबर 2026
हर आँकड़ा तिथि सहित — पूरा रिकॉर्ड वेबसाइट पर।

86

संकेतक, हर एक तिथि के साथ

32

संकेतक जिनमें 2014 के मुकाबले दोगुने से अधिक की छलांग

20

योजनाएँ और सेवाएँ जो 2014 में थीं ही नहीं — शून्य से शुरू

अर्थव्यवस्था

2013 में भारत की गिनती 'फ़्रैजाइल फ़ाइव' — दुनिया की पाँच सबसे कमज़ोर मानी गई उभरती अर्थव्यवस्थाओं — में होती थी; 2025 में भारत विश्व की शीर्ष पाँच अर्थव्यवस्थाओं में है। अर्थव्यवस्था का आकार तीन गुना से अधिक हुआ, जबकि औसत महँगाई आधी और विदेशी मुद्रा भंडार ढाई गुना हुआ — यह विस्तार स्थिरता के साथ आया है। 17 अलग-अलग करों की जगह एक जीएसटी ने ली और अप्रैल 2026 में एक महीने का जीएसटी संग्रह ₹2.42 लाख करोड़ के रिकॉर्ड पर पहुँचा। रिकॉर्ड निर्यात और एफडीआई बताते हैं कि इस वृद्धि पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ा है।

देश की अर्थव्यवस्था का आकार (जीडीपी)

×3.1

तब
₹112 लाख करोड़
अब
₹346 लाख करोड़

2013-14 → 2025-26

भारत — 'फ़्रैजाइल फ़ाइव' से 'टॉप फ़ाइव' तक

टॉप 5 में

तब
'फ़्रैजाइल फ़ाइव' में गिनती
अब
शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में

2013 → 2025

विदेशी निवेश (FDI) — 12 वर्षों में

×2.7

तब
\$313 अरब
अब
\$843 अरब

2002-14 → 2014-26

केंद्र सरकार का निर्माण-कार्यो पर खर्च (पूँजीगत व्यय)

×6.5

तब
₹1.88 लाख करोड़
अब
₹12.22 लाख करोड़

2013-14 → 2026-27 (बजट)

महँगाई दर (औसत खुदरा)

आधे से कम

तब
9.5%
अब
4.6%

2013-14 → 2024-25

कुल निर्यात (सामान और सेवाएँ)

+85%

तब
\$466 अरब
अब
\$863 अरब

2013-14 → 2025-26

विदेशी मुद्रा भंडार

×2.5

तब
\$304 अरब
अब
\$748 अरब

मार्च 2014 → 25 सितम्बर 2026

विदेश से भारत भेजा गया पैसा (रेमिटेंस)

+93%

तब
\$70 अरब
अब
\$135 अरब

2013-14 → 2024-25

जीएसटी — पहले कितने कर, अब कितने

17 कर → 1 कर

तब
17 अलग-अलग कर
अब
1 कर — जीएसटी

2017 से पहले → 1 जुलाई 2017 से



आयकर — कितनी आय तक
कोई टैक्स नहीं

×6.0

तब अब
₹2 लाख ₹12 लाख

2013-14 → 2025-26 से

कारोबार में आसानी (ईज ऑफ़
डूइंग बिज़नेस) रैंक

79 स्थान ऊपर

तब अब
142वाँ 63वाँ

2014 → 2019 (अंतिम रिपोर्ट)

गरीब कल्याण

लाभ सीधे खाते में पहुँचने से गरीबी-निवारण की गति बदली: गरीबी एक दशक में 60% से अधिक घटी, और बैंक खाता, गैस, शौचालय, नल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएँ लगभग हर घर तक पहुँचीं।

गरीबी में रहने वाली आबादी

61% कम

तब अब
29.17% 11.28%

2013-14 → 2022-23

अत्यंत गरीबी में आबादी (\$3
प्रतिदिन से कम पर)

80% कम

तब अब
27.1% 5.3%

2011-12 → 2022-23

जन धन बैंक खाते

शून्य से

तब अब
योजना नहीं थी 59.37 करोड़

2014 → 23 सितम्बर 2026

सरकारी सहायता सीधे खातों
में (DBT) — एक वर्ष में

×93

तब अब
₹7,367 करोड़ ₹6.83 लाख करोड़

2013-14 → 2024-25

घरों में गैस (एलपीजी)
कनेक्शन

×2.4

तब अब
14 करोड़ 33.13 करोड़

2014 → 1 जुलाई 2026

गाँवों में शौचालय की सुविधा

×2.6

तब अब
38.7% 100% (खुले में
शौच से मुक्त)

2 अक्टूबर 2014 → 2 अक्टूबर 2019

ऐसे गाँव जहाँ बिजली नहीं थी

हर गाँव रोशन

तब अब
18,000 से अधिक शून्य

अप्रैल 2015 → 28 अप्रैल 2018

गाँव के घरों में नल से पानी

×4.9

तब अब
3.23 करोड़ (16.7%) 15.91 करोड़
(82.2%)

अगस्त 2019 — 2014 में इससे भी कम → अगस्त 2026

आयुष्मान भारत — ₹5 लाख
तक मुफ्त इलाज का कवर

शून्य से

तब अब
योजना नहीं थी 60 करोड़ से
अधिक लाभार्थी

2018 से पहले → सितम्बर 2026

पक्के घर — पीएम आवास
योजना

शून्य से

तब अब
योजना नहीं थी 4.21 करोड़ घर

2014 → 2014-2024

मुफ्त राशन पाने वाले लोग

शून्य से

तब अब
योजना नहीं थी 81 करोड़ से अधिक
लोग

2020 से पहले → 2026

इंफ्रास्ट्रक्चर

राजमार्ग 60% बढ़े, हवाई अड्डे दोगुने से अधिक, मेट्रो चार गुना और रेल लगभग पूरी तरह विद्युतीकृत हुई; बंदरगाहों पर जहाज का टर्नअराउंड समय आधा होना बताता है कि गति के साथ दक्षता भी आई।



राष्ट्रीय राजमार्ग

+61%

तब
91,287 किमी

अब
1,46,572 किमी

2014 → दिसम्बर 2025

हाई-स्पीड सड़क गलियारे
(एक्सप्रेसवे)

*9.8

तब
550 किमी

अब
5,364 किमी

2014 → दिसम्बर 2025

चालू हवाई अड्डे

*2.2

तब
74

अब
166

2014 → सितम्बर 2026

मेट्रो नेटवर्क

*4.6

तब
248 किमी · 5 शहर

अब
1,143 किमी · 29 शहर

2014 → मार्च 2026

बिजली से चलने वाली रेल लाइनें (ब्रॉड गेज)

*3.3

तब
लगभग 21,000 रुट-किमी

अब
69,873 रुट-किमी (99.6%)

2014 → मार्च 2026

बंदे भारत सेवाएँ

शून्य से

तब
एक भी नहीं

अब
162 सेवाएँ (81 ट्रेनें)

2019 से पहले → जुलाई 2026

मालगाड़ियों के लिए अलग रेल गलियारा

शून्य से

तब
एक भी किमी नहीं

अब
2,843 किमी

2014 → 8 सितम्बर 2026

बंदरगाह पर मालवाहक जहाज का टर्नअराउंड समय (आने से माल उतार-चढ़ाकर रवाना होने तक)

आधा समय

तब
96 घंटे

अब
48 घंटे

2014 → 2025

माल-ढुलाई की क्षमता में विश्व रैंक (लॉजिस्टिक्स इंडेक्स)

16 स्थान ऊपर

तब
54वाँ स्थान

अब
38वाँ स्थान

2014 → 2023

किसान

कृषि विभाग का बजट लगभग छह गुना, समर्थन मूल्य (MSP) लगभग दोगुना और अनाज उत्पादन 40% से अधिक बढ़ा; पीएम-किसान ने आय-सहायता को बिचौलियों के बिना सीधे खाते तक पहुँचाया।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट

*6.0

तब
₹21,933 करोड़

अब
₹1,30,561 करोड़

2013-14 → 2026-27 (बजट)

अनाज का उत्पादन

+42%

तब
2,650 लाख टन

अब
3,765 लाख टन

2013-14 → 2025-26

दूध का उत्पादन

+69%

तब
146 मिलियन टन

अब
247 मिलियन टन

2014-15 → 2024-25

मछली का उत्पादन

*2.1

तब
95 लाख टन

अब
198 लाख टन

2013-14 → 2024-25

गेहूँ का समर्थन मूल्य (MSP)

+85%

तब
₹1,400 / क्विंटल

अब
₹2,585 / क्विंटल

2014-15 → 2026-27

धान का समर्थन मूल्य (MSP)

+86%

तब
₹1,310 / क्विंटल

अब
₹2,441 / क्विंटल

2013-14 → 2026-27



पीएम-किसान — किसानों के खातों में सीधी सहायता

शून्य से

तब योजना नहीं थी अब **₹4.46 लाख करोड़ (23 किस्ते)**

2019 से पहले → जून 2026

मिट्टी की जाँच के कार्ड (मृदा स्वास्थ्य कार्ड)

शून्य से

तब योजना नहीं थी अब **लगभग 26 करोड़ कार्ड**

2015 से पहले → मार्च 2026

ऑनलाइन मंडी ई-नाम से जुड़े किसान

शून्य से

तब मंच नहीं था अब **1.8 करोड़ किसान · 1,656 मंडियाँ**

2016 से पहले → मार्च 2026

डिजिटल

सस्ता डेटा और आधार-UPI-डिजिलॉकर की सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने भारत को विश्व की सबसे बड़ी रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली दी; मोबाइल निर्माण आयात से निर्यात की ओर मुड़ गया।

इंटरनेट कनेक्शन

×4.3

तब 25.15 करोड़ अब **109.28 करोड़**

मार्च 2014 → मार्च 2026

मोबाइल डेटा की कीमत

97% सस्ता

तब ₹269 / GB अब **₹7.51 / GB**

मार्च 2014 → मार्च 2026

UPI — एक वर्ष का लेनदेन

शून्य से

तब UPI नहीं था अब **₹314 लाख करोड़ · 24,162 करोड़ लेनदेन**

2016 से पहले → 2025-26

देश में बने मोबाइल फ़ोन (मूल्य)

×29

तब ₹18,900 करोड़ अब **₹5.45 लाख करोड़**

2014-15 → 2024-25

मोबाइल फ़ोन निर्यात

×133

तब ₹1,500 करोड़ अब **₹2 लाख करोड़**

2014-15 → 2024-25

मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्रियाँ

×150

तब 2 अब **300 से अधिक**

2014 → 2025

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन

×5.9

तब ₹1.9 लाख करोड़ अब **₹11.3 लाख करोड़**

2014-15 → 2024-25

मोबाइल बेस स्टेशन (BTS)

×4.8

तब 6.5 लाख अब **31.4 लाख**

2014 → 2025

पंजीकृत स्टार्टअप

शून्य से

तब स्टार्टअप इंडिया नहीं था अब **2.35 लाख से अधिक · 131 यूनिर्कॉर्न**

2016 से पहले → जून 2026

डिजिलॉकर इस्तेमाल करने वाले

शून्य से

तब सेवा नहीं थी अब **70 करोड़ से अधिक**

2015 से पहले → सितम्बर 2026

सेमीकंडक्टर (चिप) परियोजनाएँ

शून्य से

तब एक भी नहीं अब **12 परियोजनाएँ · ₹1.64 लाख करोड़**

2014 → मई 2026

स्वास्थ्य · शिक्षा

मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस सीटें दोगुने से अधिक और जन औषधि केंद्र सैकड़ों गुना हुए — पहुँच और किफ़ायत दोनों बढ़ीं; शिशु और मातृ मृत्यु दर में गिरावट इसी का परिणाम है।



मेडिकल कॉलेज

*2.2

तब अब
387 844

2014 → जुलाई 2026

एमबीबीएस सीटें

*2.7

तब अब
51,348 1,39,489

2014 → जुलाई 2026

पीजी मेडिकल सीटें

*2.8

तब अब
31,185 86,360

2014 → जुलाई 2026

एम्स

*3.3

तब अब
7 23

2014 तक → 2026

आईआईटी

+44%

तब अब
16 23

2014 → 2026

जन औषधि केंद्र

*240

तब अब
84 20,149

2014 → 30 जून 2026

विश्वविद्यालय

+78%

तब अब
723 1,289

2013-14 → 2023-24

शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जन्म)

36% कम

तब अब
39 25

2014 → 2023

प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु (प्रति लाख जन्म)

32% कम

तब अब
130 88

2014-16 → 2021-23

जन औषधि से लोगों की दवा-खर्च में बचत

शून्य से

तब अब
84 केंद्र — बचत नगण्य ₹45,000 करोड़ की बचत • 20,149 केंद्र

2014 → 12 वर्षों में • 30 जून 2026

स्टेंट और घुटना प्रत्यारोपण सस्ते होने से बचत

शून्य से

तब अब
मूल्य-नियंत्रण नहीं था लगभग ₹5,950 करोड़ प्रति वर्ष की बचत

2017 से पहले → फरवरी • अगस्त 2017 से

आयुष्मान भारत से परिवारों के इलाज-खर्च में बचत

शून्य से

तब अब
योजना नहीं थी ₹1.25 लाख करोड़ से अधिक की बचत

2018 से पहले → आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25

ऊर्जा • पर्यावरण

सौर क्षमता 60 गुना और गैर-जीवाश्म क्षमता का हिस्सा आधे से अधिक हुआ; ऊर्जा-संक्रमण और वन्यजीव संरक्षण — बाघ, सिंह, चीता — साथ-साथ आगे बढ़े।

सौर ऊर्जा क्षमता

*60

तब अब
2.8 गीगावाट 168 गीगावाट

2014 → अगस्त 2026

साफ़ ऊर्जा (गैर-जीवाश्म) का हिस्सा बिजली क्षमता में

+69%

तब अब
लगभग 32% 54% (300 गीगावाट से अधिक)

2014 → अगस्त 2026

सौर, पवन और जल से बिजली का उत्पादन

*2.5

तब अब
191 अरब यूनिट 477 अरब यूनिट

2014-15 → 2025-26

पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण

लक्ष्य से 5 वर्ष पहले

तब अब
1.5% 20%

2013-14 → 2025

एलईडी बल्ब — उजाला

शून्य से

तब अब
योजना नहीं थी लगभग 37 करोड़

2015 से पहले → 2025

बाघ

+65%

तब अब
2,226 3,682

2014 → 2022



एशियाई सिंह

+70%

तब
523 अब
891

2015 → 2025

चीता

वापसी

तब
भारत में विलुप्त
(1952 से) अब
56

2022 से पहले → सितम्बर 2026

वन और पेड़ों से ढका क्षेत्र

+4%

तब
24.16% अब
25.17%

वन स्थिति रिपोर्ट 2015 → वन स्थिति रिपोर्ट 2023

कोयला उत्पादन

+85%

तब
566 मिलियन टन अब
1,047 मिलियन टन

2013-14 → 2024-25

सुरक्षा · शासन

रक्षा निर्यात 56 गुना और रक्षा उत्पादन तीन गुना से अधिक — आत्मनिर्भरता ने सुरक्षा को उद्योग बनाया; नक्सल-प्रभावित जिले 126 से शून्य हुए।

रक्षा निर्यात

*56

तब
₹686 करोड़ अब
₹38,424 करोड़

2013-14 → 2025-26

रक्षा उत्पादन

*3.2

तब
₹46,429 करोड़ अब
₹1,50,590 करोड़

2014-15 → 2024-25

नक्सल-प्रभावित जिले

नक्सल-मुक्त
भारततब
126 अब
शून्य

2014 → 31 मार्च 2026

पूर्वोत्तर में हवाई अड्डे

+89%

तब
9 अब
17

2014 → 2026

पुराने बेकार कानून हटाए गए

सरल शासन

तब
— अब
1,600 से अधिक

2014 → 2025

विदेशी सरकारों के सर्वोच्च सम्मान

विश्वमित्र भारत

तब
— अब
36 देशों से

2014 → अगस्त 2026

नारी शक्ति

खाते, गैस, स्वयं सहायता समूह और उच्च शिक्षा — हर संकेतक में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी; 26 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश विश्व के सबसे लम्बे अवकाशों में है।

वेतन सहित मातृत्व अवकाश

*2.2

तब
12 सप्ताह अब
26 सप्ताह

2017 से पहले → 2017 से

स्वयं सहायता समूहों में महिलाएँ

*4.3

तब
2.35 करोड़ अब
10 करोड़ से अधिक

2014 → 2026

सुकन्या समृद्धि खाते

शून्य से

तब
योजना नहीं थी अब
4.53 करोड़

2015 से पहले → जनवरी 2026



लखपति दीदी

शून्य से

तब
पहल नहीं थी

अब
3 करोड़ से अधिक



2023 से पहले → अगस्त 2026

उज्ज्वला कनेक्शन (महिलाओं के नाम)

शून्य से

तब
योजना नहीं थी

अब
10.57 करोड़



2016 से पहले → सितम्बर 2026

उच्च शिक्षा में युवतियों का नामांकन (हर 100 में)

+36%

तब
22.9

अब
31.2



2014-15 → 2023-24

लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण

कानून बना

तब
प्रावधान नहीं था

अब
एक-तिहाई सीटें (कानून 2023)



2023 से पहले → 2023